रोजगार संकट का आकार

लेखक- संतोष मेहरोत्रा (प्रोफेसर, अर्थशास्त्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

13 फरवरी, 2019

"भारत के पास अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठाने के लिए कोई औद्योगिक नीति या रोजगार रणनीति उपलब्ध नहीं है।"

अंतिम प्रकाशित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) श्रम बल सर्वेक्षण के वर्ष 2011-12 के बाद से रोजगार का सृजन धीमा हो गया है। मैंने (लेखक) लेबर ब्यूरो के वार्षिक सर्वेक्षण (2015-16) के आंकड़ों और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्रा. लिमिटेड (सीएमआईई) डेटा (2016 के बाद) का उपयोग किया है, जो इस निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए एनएसएसओ श्रम बल सर्वेक्षणों से बड़े आकार का है। दोनों सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी तथा संगठित और असंगठित क्षेत्र के रोजगार को कवर करते हैं; दूसरे शब्दों में कहें तो ये दोनों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन/राष्ट्रीय पेंशन योजना (संगठित) के साथ-साथ ऐसे रोजगार को भी शामिल करते हैं, जिसे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (MUDRA) ऋण या मंच अर्थव्यवस्था नौकरियों द्वारा उत्पन्न किया गया है। हमने बार-बार कहा है कि रोजगार पर अच्छे डेटा के अभाव के सरकारी दावे केवल मनगढ़ंत कहानी हैं।

एनएसएसओ 2017-18 के आंकड़ों के लीक होने से पहले के मेरे (लेखक) विश्लेषण से पता चलता है कि 2012 से नौकरियों की स्थिति वाकई में गंभीर होती गई है।

एक लंबी छलांग

लीक हुए एनएसएसओ 2017-18 के आंकड़ों से पता चलता है कि खुली बेरोजगारी की दर (जो सामान्य स्थिति में प्रच्छन्न बेरोजगारी और अनौपचारिक खराब गुणवत्ता वाली नौकरियों को नहीं मापती है) सामान्य स्थिति से 1977-78 और 2011-12 के बीच कभी भी 2.6% से अधिक नहीं हुई, जो अब 2017-18 में बढ़कर 6.1% हो गयी है। पिछले 10-12 वर्षों में, अधिक संख्या में युवा शिक्षित हुए हैं।

तृतीयक शिक्षा नामांकन दर (18-23 आयु वर्गों के लिए) 2006 में 11% से बढ़कर 2016 में 26% हो गई। 15-16 आयु वर्ग के लोगों के लिए सकल माध्यमिक (कक्षा 9-10) नामांकन दर 2010 में 58% से बढ़कर 2016 में 90% हो गई। ये युवा शहरों में उद्योग या सेवा क्षेत्रों में नियमित नौकरी करना चाहते हैं, न कि कृषि क्षेत्र में। यदि उनके पास ऐसे स्तरों तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सुविधा है, तो वे बेरोजगार रहने का भी 'खर्च' उठा सकते हैं। लेकिन गरीब लोग, जो बहुत कम शिक्षित होते हैं, उनके पास खुली बेरोजगारी को झेलने की क्षमता भी कम होती है,इसलिए उनकी खुली बेरोजगारी दर भी कम है।

एनएसएसओ 2017-18 यह भी दर्शाता है कि जैसे-जैसे खुली बेरोजगारी की दर बढ़ी है, वैसे-वैसे अधिक से अधिक लोग निराश होते गए हैं और श्रम बल से बाहर हो गए; दूसरे शब्दों में कहें, तो उन्होंने काम की तलाश करना ही बंद कर दिया। नतीजतन सभी उम्र के लिए श्रम बल की भागीदारी दर (LFPR यानी वैसे लोग जो काम की तलाश में हैं) 2004-05 में 43% से गिरकर 2011-12 में 39.5% हो गई, जो 2017-18 में 36.9% हो गई। यह उन युवाओं की बढ़ती संख्या को दर्शाता है जो NEET (not in education] employment or training) हैं अर्थात नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग या शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं हैं। ये हमारे जनसांख्यिकीय लाभांश का एक संभावित स्रोत हैं, लेकिन अब ये बढ़ती जनसांख्यिकीय आपदा की तरह प्रतीत हो रहे हैं।

इस बीच, सरकार के अर्थशास्त्रियों द्वारा हमें बार-बार बताया जाता रहा है कि रोजगार संकट है ही नहीं।

2004-05 और 2011-12 के बीच, हर साल 7.5 मिलियन नए गैर-कृषि रोजगार सृजित किए जा रहे थे। बेरोजगारी की दर केवल 2.2% थी। 2011-12 तक खुली बेरोजगारी की मात्रा लगभग स्थिर (लगभग 10 मिलियन) थी, लेकिन 2015-16 तक यह बढ़कर 16.5 मिलियन हो गई। 2011-12 के बाद खुली बेरोजगारी में वृद्धि से पता चलता है कि 2011-12 से पहले शिक्षित लोगों ने गैर-कृषि रोजगार की तलाश शुरू की, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला। नवीनतम एनएसएसओ डेटा बताते हैं कि यह स्थिति 2017-18 तक और खराब हो गई।

शिक्षा श्रेणियों के पार

शिक्षितों की बेरोजगारी दर में भारी वृद्धि (वार्षिक सर्वेक्षण, श्रम ब्यूरो के हमारे अनुमानों के आधार पर) के आंकड़ों पर सरकार को कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता थी। मेरा (लेखक) अनुमान है कि मध्यम शिक्षा (कक्षा 8) वाले लोगों के लिए बेरोजगारी दर 2011-12 से 2016 तक 0.6% से 2.4% हो गई थी; कक्षा 10 पास करने वालों के लिए ये आंकड़े 1.3% से 3.2% हो गये थे;

कक्षा 12 पास करने वालों के लिए ये आंकड़े 2% से 4.4% हो गये थे, स्नातकों के लिए ये आंकड़े 4.1% से 8.4% हो गये थी, और पोस्ट-ग्रेजुएट के लिए ये आंकड़े 5.3% से 8.5% हो गये थे। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि तकनीकी शिक्षा वालों के लिए बेरोजगारी दर 6.9% से बढ़कर 11% हो गई, पोस्ट-ग्रेजुएट (तकनीकी शिक्षा में) के लिए 5.7% से 7.7% और व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित के लिए 4.9% से 7.9% हो गयी।

भारत के विकास के चरण में एक अर्थव्यवस्था के लिए, कृषि में श्रमिकों की वृद्धि (1999-2004 में 20 मिलियन हुई) वांछित के विपरीत दिशा में एक संरचनात्मक प्रतिगमन है। 2004-05 और 2011-12 के बीच, भारत के आर्थिक इतिहास में पहली बार कृषि में श्रमिकों की संख्या तेजी से गिरी, जो अच्छी बात है। इसी तरह, 2004-05 और 2011-12 के बीच कृषि में कार्यरत युवाओं की संख्या (15-29 वर्ष) 86.8 मिलियन से घटकर 60.9 मिलियन (3 मिलियन प्रति वर्ष की दर से) हो गई। हालांकि, 2012 के बाद, जैसे ही गैर-कृषि रोजगार में वृद्धि हुई, कृषि में युवाओं की संख्या वास्तव में 2015 तक 84.8 मिलियन हो गई। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि ये युवा पहले समूह से बेहतर शिक्षित थे, लेकिन ये कृषि में रहने के लिए मजबूर थे।

विनिर्माण नौकरियों में गिरावट

इससे भी बदतर, विनिर्माण रोजगार वास्तव में निरपेक्ष रूप से गिर गया, जो 2011-12 में 58.9 मिलियन से 2015-16 में 48.3 मिलियन हो गया, अर्थात् इन चार साल की अवधि में 10.6 मिलियन की गिरावट। यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में धीमी वृद्धि के साथ संगत है, जिसमें विनिर्माण, खनन और बिजली शामिल हैं। आईआईपी (2004-05 श्रृंखला में) 2004-05 में 100 से बढ़कर 2013-14 में 172 तक तेजी से वृद्धि हुई थी, लेकिन केवल 2011-12 में 100 के आधार से बाद की श्रृंखला में 2013-14 में 107 और 2017-18 में 125.3 पर पहुंच गयी। यह 2013 के बाद पहली बार गिरते हुए निर्यात के साथ भी संगत है। यह 2013 के बाद से निवेश से जीडीपी अनुपात में तेजी से गिरने के साथ भी संगत है और यह 2013 के स्तर से अभी भी नीचे है। यह निजी और सार्वजनिक निवेश दोनों के लिए है।

मेरा (लेखक) अनुमान है कि श्रम बल (वर्तमान में कम से कम 5 मिलियन प्रति वर्ष) में नए प्रवेशकों की संख्या और विशेष रूप से शिक्षित बल श्रम 2030 तक बढ़ जाएंगे। चीन ने अपनी औद्योगिक रणनीति से जुड़ी एक रोजगार रणनीति (जो शिक्षा और कौशल नीति द्वारा जुड़ा हुई है) को डिजाइन करके गरीबी को तेजी से कम करने में कामयाबी हासिल की है। दुर्भाग्य से, भारत के पास न तो कोई औद्योगिक नीति है और न ही कोई रोजगार रणनीति।

GS World टीम...

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में देश में रोजगार से जुड़ी नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) की एक रिपोर्ट लीक हुई।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2017-18 में बेरोजगारी दर 45 साल में सबसे ज्यादा 6.1% के स्तर पर पहुंच गई है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 की बेरोजगारी दर 1972-73 के बाद सबसे ज्यादा है।
- देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 7.8 फीसदी जबकि ग्रामीण इलाकों में 5.3 फीसदी है।
- 15-29 साल के शहरी पुरुषों के बीच बेरोजगारी की दर 18.7 फीसदी है। 2011-12 में ये दर 8.1 फीसदी थी।
- 2017-18 में शहरी महिलाओं में 27.2 फीसदी बेरोजगारी है जो 2011-12 में 13.1 फीसदी थी।
- एनएसएसओ सर्वे के अनुसार वर्ष 2011-12 यह देश में बेरोजगारी दर 2.2 प्रतिशत थी।

शहरी क्षेत्रों में

- पिछले सालों की तुलना में अभी देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या काफी अधिक है और यह कुल जनसंख्या के मुकाबले बहुत अधिक है।
- शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों से भी ज्यादा रही। यहाँ बेरोजगारी दर पुरुषों में 18.7 प्रतिशत और महिलाओं में 27.2 प्रतिशत रही।
- पीएलएफएस एनएसएसओ का पहला सालाना हाउसहोल्ड सर्वे है, जिसके लिए जुलाई, 2017 से जून, 2018 के दौरान आंकड़े जुटाए गए थे।
- 2017-18 में महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) में गिरावट देखी गई और यह 23.3 फीसदी रही, जबकि वित्त वर्ष 2011-12 में यह 31.2 फीसदी और 2009-10 में 32.6 फीसदी रही।
- पुरुषों के लिए एलएफपीआर 2011-12 में 79.8 फीसदी था जो 2017-18 में 75.8 फीसदी रह गया। इसका मतलब है कि पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाएं श्रम नौकरियों से बाहर हो रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में

- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर 2017-18 में 13.6 प्रतिशत रही, जो 2011-12 में 4.8 प्रतिशत थी।
- शिक्षित ग्रामीण महिलाओं में 2004-05 से 2011-12 तक बेरोजगारी दर 9.7 प्रतिशत से 15.2 प्रतिशत के बीच रही है। 2017-18 में यह बढ़कर 17.3 प्रतिशत हो गई।
- शिक्षित ग्रामीण पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गई, जो 2004-05 से 2011-12 के दौरान 3.5-4.4 प्रतिशत के बीच रही।

- ग्रामीण क्षेत्रों में 15-29 आयु वर्ग के युवाओं में 2011-12 के दौरान बेरोजगारी दर 5 प्रतिशत थी, जो 2017-18 में तीन गुना से ज्यादा बढ़कर 17.4 प्रतिशत हो गई।

क्या है?

- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के नाम से भी जाना जाता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी।
- यह भारत का सबसे बड़ा संगठन है, जो नियमित रूप से देश का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करता है।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

क्या कहा नीति आयोग ने?

- ऐसा कोई भी डेटा सरकार की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है।
- सरकार तिमाही डेटा पेश करेगी।
- एनएसएसओ का डेटा पूरी तरह से गलत है।
- नीति आयोग के मुताबिक 7-7.8 मिलियन नौकरियां दी गई हैं।
- देश को अभी 7 मिलियन नौकरियों की जरूरत है।
- मार्च तक नीति आयोग रिपोर्ट जारी करेगा
- रोजगार को लेकर अभी आंकड़े तैयार हो रहे हैं।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एनएसएसओ 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार खुली बेरोजगारी दर बढ़कर 6.1% हो गयी है।
2. एनएसएसओ 2017-18 के आंकड़ों में तृतीयक शिक्षा नामांकन दर 2006 की अपेक्षा 2016 में बढ़ी है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

1. Consider the following statements-

1. According to the data of NSSO, 2017-18, the open employment has increcsed to 6.1%.
2. According to the data of NSSO, 2017-18, the tertiary education enrollment has increased in 2016 than 2006.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: हाल ही में एनएसएसओ 2017-18 के आंकड़ों के लीक होने से पता चला है कि 2012 के पश्चात् रोजगार के क्षेत्र में भारी गिरावट आयी है। इन सभी स्थितिओं से निपटने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई जानी चाहिए? चर्चा कीजिए।

Q. According to the leaked data of the NSSO, 2017-18, the situation of huge decline in the employment after 2012 has been Seen. Which types of strategies should be adopted to tackle this situation? Discuss.

(250 Words)

नोट : 12 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।